भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23305700, **फैक्स** : 23005787

<u>भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा संसद सदस्य</u>
<u>श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य</u>

दिनांक : 24 सितम्बर, 2008

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव – विशेषकर वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले गंभीर संकट का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। राजनीतिक नेताओं के लिए सबक यह है कि जब तक अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तथा सरकार की वित्तीय नीति से विधिवत पोषित नहीं होगी तब तक उसको सस्ती मुद्रा की खुराक द्वारा पुष्ट करने के कृत्रिम उपाय दीर्घावधि में सहायक नहीं हो सकते हैं। इससे यह सबक भी मिलता है कि यदि सभी बड़ी वित्तीय तथा बैंकिग कम्पनियों को किसी विनियम के अभाव में अव्यवस्था पैदा करने की खुली छूट मिल जाए तो ऐसा संकट पैदा होना लाज़मी है। आवासीय ऋण जाने बिना बार–बार क्रय – विक्रय किया गया कि कौन वास्तविक उधार देने वाला था, कौन प्रतिभूति जारी कर रहा था और कौन इसका क्रय अथवा विक्रय कर रहा था। इसके चलते मोर्गन स्टेनली, सिटी बैंक और यूबीएस जैसे बैंकों को करोड़ों डॉलरों का अवमूल्यन करना पड़ा था। लेहमन ब्रदर्स जैसी विराट संस्थाएं दिवालिया हो गई हैं, बैंक बिक गए हैं और अनेकों बीमा कम्पनियां अंतिम सांसें ले रही हैं।

अमेरिका के वित्तीय संकट ने कई अन्य अर्थ–व्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। भाजपा सरकार से इतना चाहेगी कि वह राष्ट्र को बताए कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय कर रही है कि अमेरिका का वित्तीय संकट हमारे देश के बैंकिग तथा वित्तीय क्षेत्र को गंभीर रूप में प्रभावित नहीं कर पाए। क्या यह ऐसा समय है जब वित्तीय क्षेत्र में सुधारों – विशेषकर भारतीय बैंकों में विदेशी निवेशकों को देने के लिए प्रस्तावित अहम अधिकारों की रूपरेखा को प्रकाश में लाया जाए, जैसाकि कई विशेषज्ञ समितियों ने प्रस्ताव किया है ? भाजपा मांग करती है कि इस बारे में उपयुक्त समय रहते उपाय किए जाएं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था कि हितों पर वर्तमान वैश्विक संकट की छाया न पड़े। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जून में समाप्त हुई तिमाही के परिणाम के अनुसार निर्माण क्षेत्र की वृद्धि काफी कम अर्थात 5.2 प्रतिशत रह गई थी और हो सकता है कि वर्तमान वैश्विक संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण–योग्य धन सुलभ ही न हो – चाहे इस बारे में कुछ भी उपाय कर लिए जाएं। भारत में ऋण लेना ऊंची ब्याज दरों के कारण महंगा हो गया है तथा मुद्रास्फीति को काबू करने में संप्रग सरकार ने जो एकमात्र विकल्प पेश किया है, वह है ब्याज दरों का परिशोधन। यह पूरी तरह साफ है कि सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा है और न ही सरकार के पास मुद्रास्फीति, जो 13 वर्षों में सबसे ऊंची 12.14 प्रतिशत बनी हुई है, को नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति ही बची है। इसीलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के घोर कु–प्रबंधन के कारण विनिर्माण – क्षेत्र नुकसान उठाता रहेगा। यह संकट निर्यात क्षेत्र, जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा।

भाजपा लघु निवेशकों के हितों की प्रबल समर्थक रही है किंतु स्टॉक मार्केट के मोर्चे पर स्थिति विकराल बनी हुई है। सितम्बर में भड़के अमरीकी वित्तीय संकट के पश्चात् विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय स्टॉक मार्केट से लगभग 2 बिलियन डॉलर वापस निकाल लिए हैं। मगर उल्लेखनीय यह बात है कि जनवरी से सितम्बर 2008 के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8 बिलियन डॉलर रकम वापस निकाल ली। सरकार को इन संकेतों को समझ लेना चाहिए था। क्या हम उसी तरह की खुली अव्यवस्था को न्यौता देना चाहते हैं, जिसके कारण अमरीकी संकट पैदा हुआ था या क्या सरकार दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पा रही है ? भाजपा इस बात पर भी समान रूप से चिंतित है कि इस संकट के कारण पेशेवर भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आ रही है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह इस समय अमरीका में हैं और उन्हें वहां पर यह मामला उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए।

भाजपा को आशंका है कि वैश्विक वित्तीय संकट तथा साथ ही नाजुक हालत में पहुंची भारत की अर्थव्यवस्था जोकि संप्रग सरकार के अकुशल प्रबंधन के कारण नाजुक बनी है, से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस स्थिति में आम आदमी की तकलीफें और अधिक बढ़ जाएंगी।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी